



सं.11/2/2014-वीएस-(सीआरएस)/751

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S. Division, West Block-1, R.K.Puram, New Delhi-110066

दूरभाष-26104012

ई-मेल-drg-crs.rgi@censusindia.gov.in



दिनांक: 25.03.2015

सेवा में,

सभी मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु

**विषय: जन्म और मृत्यु का पंजीकरण तथा उसका प्रमाण पत्र जारी करने में व्याप्त अनियमितताएं एवं भ्रष्ट तरीके अपनाना।**

महोदय,

जैसाकि आप जानते हैं जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा किए गए आदेशों के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। आरबीडी अधिनियम की धारा 7 और 21 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा ऐसे सभी जन्म (मृत जन्म सहित) और मृत्यु का पंजीकरण किया जाना अपेक्षित है जोकि उसके क्षेत्राधिकार में हुए हों। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान के अन्तर्गत पंजीकरण का कार्य संपन्न होते ही रजिस्ट्रार द्वारा सूचनादाता को जन्म/मृत्यु रजिस्ट्रारों से संबंधित उद्धरण/प्रमाणपत्र जारी किया जाना भी अपेक्षित है।

2. आप इस बात से सहमत होंगे कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण तथा उद्धरण/प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी अनिवार्य प्रावधानों के बावजूद भी यह देखा गया है कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में तथा वांछित जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने में जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है। इस कार्यालय को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण तन्त्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में अनेक शिकायतें/अभ्यावेदन अनेक राज्यों से प्राप्त हुए हैं। यह भी देखा गया है कि जन्म और मृत्यु के प्रमाणपत्र प्राप्त

450 (vital)  
11/8

करने के लिए रजिस्ट्रेशन कार्यकर्ताओं को घूस दी जा रही है। भ्रष्टाचार की ये शिकायतें प्रधान मंत्र कार्यालय तक पहुंची हैं और प्रधान मंत्री कार्यालय ने इसको बहुत गंभीरतापूर्वक लिया है।

3. सफल और नागरिक अनुकूल सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली को दोष रहित बनाने के लिए आप जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण तथा उद्धरण/प्रमाणपत्र जारी करने के वर्तमान तन्त्र के अन्तर्गत व्याप्त घूसखोरी को रोकने के लिए ठोस प्रयास करने तथा उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है। ताकि आम जनता को निर्धारित समय सीमा के भीतर जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। राज्य सरकारों से यह अनुरोध है कि इस दिशा में निम्न कदम उठाए जाएं :-

- i. जन्म और मृत्यु के पंजीकरण अथवा जनता को प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करना। कानूनी कार्यवाही के विकल्प पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- ii. जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी एक पारदर्शी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए जिसमें पंजीकरण (विलम्बित पंजीकरण सहित) करने और जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्रों को जारी करने के संबंध में समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
- iii. एक स्थानांतरण नीति तैयार की जानी चाहिए, विशेष रूप से ऐसे कर्मियों के लिए जोकि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कार्य में प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़े हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी पद पर एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
- iv. अपने क्षेत्राधिकार में होने वाले किसी भी जन्म अथवा मृत्यु का बिना किसी उचित कारण के पंजीकरण करने की अनदेखी करने अथवा मना करने वाले अथवा निर्धारित मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने वाले किसी भी रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार पर आरबीडी अधिनियम की धारा 23(2) के अन्तर्गत निर्धारित शास्तियां लगाई जानी चाहिए।

4. इस संबंध में आपसे प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है। इस मामले में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए, इस संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जाए।

भवदीया,

पी. ए. मिनी

(पी. ए. मिनी)

उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)